



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 177]
No. 177]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 30, 2008/कार्तिक 8, 1930
NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 30, 2008/KARTIKA 8, 1930

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 24 अक्टूबर, 2008

सं. टीएएमपी/23/2003-डब्ल्यूएस.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48, 49 और 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा संलग्न आदेशानुसार, महापत्तन न्यासों और महापत्तन न्यासों में प्रचालन कर रहे निजी टर्मिनलों की प्रशुल्क निर्धारण कार्यवाही में अनुसरित मौजूदा दृष्टिकोण/पद्धति के कुछ क्षेत्रों पर विशोधन अधिसूचित करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएएमपी/23/2003-डब्ल्यूएस

आदेश

(सितम्बर, 2008 के 30वें दिन पारित)

एक निजी टर्मिनल प्रचालक द्वारा दाखिल की गई समीक्षा याचिका से संबंधित प्रशुल्क कार्यवाही में, इस प्राधिकरण ने पाया कि राजपत्र सं. 39 दिनांक 31 मार्च, 2005 द्वारा 31 मार्च, 2005 को इस प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित प्रशुल्क दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, लागत जमा दृष्टिकोण के अधीन, प्रशुल्क निर्धारण के लिए मौजूदा अंगीकृत दृष्टिकोण और अनुसरित पद्धति के कुछ क्षेत्रों में सुधार करने/शोधन करने की जरूरत है।

2. लागत जमा पद्धति के अधीन प्रशुल्क के निर्धारण में अनुसरित पद्धति और मौजूदा अंगीकृत दृष्टिकोण के निम्नलिखित क्षेत्र सुधार/विशोधन के लिए प्रकट हुए—

- (क). प्रशुल्क प्रस्तावों को प्रस्तुत करना;
- (ख). थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) और नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ (आरओसीई) लागू करना;
- (ग). विदेशी मुद्रा विनिमय दर;
- (घ). कार्यगत पूंजी के रूप में सुविचारित की जाने वाली विविध देनदारियों का स्तर;
- (ङ). वास्तविक और प्रत्यक्ष निष्पादन व्ययों को प्रस्तुत करना।

चूंकि विनिहित मुद्दे सामान्य प्रकृति के हैं, इसलिए इन्हें अन्य निजी टर्मिनलों और पत्तन न्यासों पर समान रूप से लागू किया जा सकता है।

3. ऊपर सूचीबद्ध मुद्दों का नीचे विश्लेषण किया गया है:—

(क). प्रशुल्क प्रस्तावों को प्रस्तुत करना:

- (i). प्रशुल्क दिशा-निर्देशों का खंड 3.1.2 इस प्राधिकरण से अपेक्षा करता है कि संशोधन के लिए प्रशुल्क प्रस्तावों को प्रस्तुत करने के लिए समय तालिका निर्धारित करे। जब तक समय तालिका निर्धारित की जाती है, मौजूदा प्रशुल्क के संशोधन के लिए प्रस्ताव संशोधन के लिए देय तारीख से कम से कम 3 महीने पहले अर्पित कर दिए जाने चाहिए। प्रस्तावों को प्रस्तुत करने के लिए कोई विशिष्ट समय तालिका अभी तक निर्धारित नहीं की गई है।
- (ii). यह देखा गया है कि अधिकांश मामलों में, प्रशुल्क प्रस्ताव मौजूदा प्रशुल्क वैधता चक्र की समाप्ति के 3 महीने पहले दाखिल नहीं किए जाते हैं। चूंकि प्रस्ताव विभिन्न तारीखों को दाखिल किए जाते हैं, इसलिए वृद्धि, नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ (आरओसीई) और विदेशी मुद्रा विनिमय दर के लिए एकसमान थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) लागू करना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा, तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष के वार्षिक आंकड़े भी प्रस्तावकों द्वारा नहीं भेजे जाते हैं। उदाहरणार्थ, फरवरी 2008 में दाखिल प्रस्ताव पर मई/जून, 2008 में निर्णय लिया जाता है जिसमें केवल वर्ष 2006-07 तक के वास्तविक आंकड़े शामिल किए जाते हैं, भले ही संशोधित दरें वित्तीय वर्ष 2008-09 से लागू हों। इसमें वास्तविकताओं के आधार पर निर्धारित नहीं किए जा रहे वर्ष 2007-08 के वित्तीय आंकड़े छूट जाते हैं।
- (iii). अतः एक वित्तीय वर्ष में प्रशुल्क प्रस्ताव दाखिल करने के लिए समय सीमा निर्धारित करना जरूरी है। पत्तनों और टर्मिनलों को प्रशुल्क प्रस्ताव उस वित्तीय वर्ष के 30 जून तक दाखिल कर देने चाहिए जिसमें प्रशुल्क संशोधन देय हो। ऐसे प्रस्ताव के साथ पिछले वित्तीय वर्ष तक के वास्तविक आंकड़े भेजने चाहिए। उदाहरणार्थ, दिसम्बर 2005 में कखग पत्तन के लिए निर्धारित प्रशुल्क दिसम्बर, 2008 में संशोधन के लिए देय होगा। अतः कखग पत्तन को पिछले वित्तीय वर्ष 2007-08 तक के वास्तविक आंकड़े और 3 वर्षों की अगली प्रशुल्क वैधता अवधि के पूर्वानुमान देते हुए अपना प्रशुल्क प्रस्ताव 30 जून, 2008 से पहले दाखिल करना चाहिए।
- (iv). प्रशुल्क की वैधता के विस्तार के लिए अनुरोध पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक समयानुसार प्रशुल्क प्रस्ताव दाखिल नहीं किए जाने के लिए पर्याप्त उपयुक्त कारण नहीं दिए जाते हैं। आपवादिक मामलों में भी जहां ऐसे अनुरोध पर विचार किया जाता है, यह प्राधिकरण मौजूदा दर में तदर्थ कटौती करेगा और इसे किसी मामले में विस्तारित अवधि के लिए लागू करने की अनुमति देगा वह 3 माह से अधिक नहीं होगी। विस्तार प्रदान करना भी इस शर्त के अधीन होगा कि विस्तारित अवधि के दौरान प्रोद्भूत अतिरिक्त अधिशेष, यदि कोई हो, अगले प्रशुल्क संशोधन में समायोजित किया जाएगा।

(ख). डब्ल्यूपीआई और आरओसीई लागू करना:

- (i). वर्ष 2005 के प्रशुल्क दिशा-निर्देशों का खंड 2.5.1, साथ ही साथ, विनिर्दिष्ट करता है कि व्यय पूर्वानुमान भारत सरकार द्वारा घोषित सभी घटकों के लिए डब्ल्यूपीआई के मौजूदा संघटन के संदर्भ में मूल्य उतार-चढ़ाव के लिए समायोजित यातायात के अनुसार होने चाहिए। प्रशुल्क दिशा-निर्देशों का खंड 2.9.2 निर्धारित करता है कि नियोजित पूंजी पर स्वीकार्य प्रतिलाभ की प्रमुख पैरामीटरों में बदलावों के आलोक में वित्तीय वर्ष की शुरुआत में समीक्षा की जाएगी।
- (ii). यह प्राधिकरण उस वर्ष के लिए यथा लागू डब्ल्यूपीआई और आरओसीई लागू करेगा जिसमें अनुमोदित संशोधित प्रशुल्क प्रभावी होगा।

- (iii). आपवादिक मामलों में, जब वित्तीय वर्ष में कोई बदलाव इस प्राधिकरण द्वारा किसी मामले में निर्णय लेने और ऐसे निर्णय की अधिसूचना की तारीख के बीच होता है, और यदि डब्ल्यूपीआई के मूल्यों और आरओसीई की महत्वपूर्ण अवधि में प्रशुल्क दिशा-निर्देशों के अनुसार संशोधित किया जाता है, संबद्ध प्रशुल्क आदेश की आरओसीई के लागू मूल्य और वार्षिक वृद्धि कारक को सही प्रकार से दर्शाए जाने की सीमा तक समीक्षा की जाएगी।

(ग). विदेशी मुद्रा विनिमय दर

- (i). मौजूदा व्यवस्था में, इस प्राधिकरण द्वारा प्रशुल्क मामले की लागत समीक्षा के निष्कर्ष के समय प्रचलित विदेशी मुद्रा विनिमय दर लागत अनुमानों को तैयार करने के लिए सुविचारित की जाती है। हालांकि प्रशुल्क दिशा-निर्देश महापत्तनों और निजी टर्मिनलों को अगली प्रशुल्क वैधता अवधि में विदेशी मुद्रा विनिमय में समाविष्ट भिन्नता को विधिवत् लागू करते हुए अपने आय अनुमानों को तैयार करने की अनुमति प्रदान करते हैं, यह देखा गया है कि सामान्यतः आय अनुमान विदेशी मुद्रा विनिमय में भावी बदलावों पर विचार करते हुए तैयार नहीं किए जाते हैं। अगले 3 वर्षों की अवधि में विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में उतार-चढ़ावों को विश्वासपूर्वक देख पाना मुश्किल होगा।
- (ii). यह प्राधिकरण सरकार से पहले ही अनुरोध कर चुका है कि कुछ पत्तन प्रशुल्क मदों को डॉलर में मूल्यवर्गित करने परंतु भारतीय रूप में वसूल करने की अपनी नीति की समीक्षा करे। सरकार द्वारा लिए जाने वाले संशोधित नीति निर्णय को लंबित रखते हुए, यह जरूरी है कि कम से कम विदेशी मुद्रा विनिमय में उतार-चढ़ावों को लेखा में लिया जाए जोकि इस प्राधिकरण द्वारा इसका विश्लेषण किए जाने के समय और भारत के राजपत्र में संशोधित प्रशुल्क की अधिसूचना के बीच होते हैं। यह प्राधिकरण संशोधित प्रशुल्क की अधिसूचना की तारीख को प्रचलित विदेशी मुद्रा विनिमय के आधार पर सुविचारित लागत अनुमानों की समीक्षा की जाएगी, यदि विश्लेषण में विश्वस्त दर और अधिसूचना की तारीख को प्रचलित दर के बीच भिन्नता (+)/(-) 2% अधिक हो। ऐसी समीक्षा कार्यवाही संबद्ध पत्तन न्यासों/निजी टर्मिनल द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर अथवा इस प्राधिकरण द्वारा अपनी ओर से शुरू की जा सकती है।

(घ). कार्यगत पूंजी के रूप में सुविचारित की जाने वाली विविध देनदारियों का स्तर

- (i). प्रशुल्क दिशा-निर्देशों का खंड 29.9 दो माह की संपदा और भारतीय रेलवे द्वारा रेलवे टर्मिनल प्रम्भरों की सीमा कार्यगत पूंजी के रूप में सुविचारित किए जाने के लिए विविध देनदारी स्तर रूप में निर्धारित करता है। चूंकि निजी टर्मिनल प्रचालक अपने कब्जे के अधीन संपदा पट्टे पर नहीं देते हैं, इसलिए उन्हें संपदा संबंधित आय प्रोद्भूत नहीं होती है। इसी प्रकार, वे रेलवे गतिविधि भी नहीं करते हैं और इसलिए भारतीय रेलवे द्वारा उन्हें टर्मिनल प्रभार देय नहीं हैं। परिणामस्वरूप, निजी टर्मिनल प्रचालकों के मामले में विविध देनदारियां शेष सदैव शून्य आती हैं। इसके विपरीत, कुछ पूर्व-भुगतान और अग्रिम होते हैं जिन्हें निजी टर्मिनल प्रचालक को संबद्ध लाइसेंस करार द्वारा यथा अपेक्षित किया जाना होता है। हालांकि ऐसे भुगतान निजी प्रचालकों के लेखा बहियों में विविध देनदारियां और अग्रिम के अधीन दर्शाए जाते हैं, वे प्रशुल्क दिशा-निर्देशों के मद्देनजर प्रशुल्क निर्धारण प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त नहीं हैं।
- (ii). यह उल्लेखनीय है कि प्रशुल्क दिशा-निर्देशों का खंड 29.9 इस प्राधिकरण को अनुमति देता है कि कार्यगत पूंजी की विभिन्न मदों की उपयुक्तता की जाँच करे। लाइसेंस करार के अनुसार निजी प्रचालकों द्वारा किए जाने वाले पूर्व-भुगतान और अग्रिम अनिवार्य सांविधिक दायित्व हैं। अतः ऐसे भुगतान को उस सीमा तक विविध देनदारियों के लिए सीमा रूप में स्वीकार करना उपयुक्त है जो पास-थू रूप में अन्यथा स्वीकार्य हों। किसी असंगतता से बचने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि भूस्वामी पत्तन को राजस्व हिस्सेदारी/रॉयल्टी का अग्रिम भुगतान विविध देनदारियों के रूप में केवल यदि ऐसी राजस्व हिस्सेदारी/रॉयल्टी की सीमा तक प्रशुल्क में पास-थू रूप में सुविचारित किया जाता है।

(ङ). वास्तविक प्रत्यक्ष और वित्तीय निष्पादन को प्रस्तुत करना

- (i). प्रशुल्क दिशा-निर्देशों का खंड 2.13 अपेक्षा करता है कि निर्धारित प्रशुल्क वैधता अवधि की समाप्ति पर वास्तविक प्रत्यक्ष और वित्तीय निष्पादन की समीक्षा की जाए और भिन्नता को निर्धारित तरीके से भावी रूप में समायोजित किया जाए। यह देखा गया है कि तीन वर्षों की अवधि के पश्चात् ऐसी समीक्षा करने से महापत्तन न्यासों/वहां पर प्रचालन कर रहे निजी टर्मिनलों अथवा उपयोक्ताओं, जो भी स्थिति हो, को शीघ्र राहत प्रदान नहीं की जा सकती है, यदि महत्वपूर्ण भिन्नता प्रशुल्क वैधता चक्र के शुरुआती चरण में देखी जाती है। अतः लगातार अनुवीक्षण के लिए प्रणाली बनाकर बेहतर व्यवस्था हो सकती है।
- (ii). पत्तन न्यासों और निजी टर्मिनल प्रचालकों से अपेक्षा की जाती है कि किसी वर्ष की प्रत्येक तिमाही के पूरा होने के 15 दिनों के भीतर वास्तविक प्रत्यक्ष और वित्तीय निष्पादन की रिपोर्ट भेजी जाए। ऐसी तिमाही रिपोर्टें प्रत्येक वर्ष के 30 जून, 30 सितम्बर, 31 दिसम्बर और 31 मार्च को समाप्त अवधि के लिए उसी प्रारूप में भरे जाते हैं जिसमें प्रशुल्क प्रस्तावों के लिए लागत विवरण भरे जाते हैं। रिपोर्ट के साथ प्रभावी प्रशुल्क निर्धारित करने के लिए विश्वास किए गए अनुमानों से भिन्नता के

कारण भी होने चाहिए। यदि दो क्रमिक तिमाही अवधि के लिए वास्तविक और अनुमानों के बीच $(+)/(-)$ 20% की भिन्नता देखी जाती है तो यह प्राधिकरण संबद्ध पत्तन न्यास/निजी टर्मिनल प्रचालकों को प्रशुल्क की अनुसूची समीक्षा किए जाने के लिए अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहेगा। यदि संबद्ध पत्तन न्यास अथवा निजी टर्मिनल प्रचालक इस प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली समय-सीमा के भीतर प्रशुल्क प्रस्ताव दाखिल करने में असफल रहता है, प्रशुल्क की समीक्षा करने के लिए अपनी ओर से कार्यवाही शुरू की जाएगी।

4. चूंकि ऊपर विश्लेषित मुद्दे मौजूदा अंगीकृत दृष्टिकोण और प्रशुल्क निर्धारण के लिए अनुसरित प्रक्रियाओं का केवल विशोधन है और प्रशुल्क दिशा-निर्देशों के किसी उपबंध के पुनर्निर्धारण के लिए नहीं है, इसलिए शेरधारकों के साथ अलग-से परामर्श प्रक्रिया नहीं अपनाई गई थी।

5. परिणामस्वरूप, और उपर्युक्त कारणों से, और समग्र विचार-विमर्श के आधार पर, यह प्राधिकरण निम्नलिखित निर्णय देता है:-

- (i). (क). महामत्तन न्यासों और निजी टर्मिनलों को प्रशुल्क प्रस्ताव उस वित्तीय वर्ष के 30 जून तक दाखिल करने होंगे जिसमें प्रशुल्क संशोधन देय होता है। ऐसे प्रस्ताव के साथ पिछले वित्तीय वर्ष तक के वास्तविक आँकड़े होने चाहिए।

(ख). प्रशुल्क की वैधता के विस्तार के लिए अनुरोध पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक प्रशुल्क प्रस्ताव समयानुसार दाखिल नहीं करने के पर्याप्त उचित कारण नहीं दिए जाते। आपवादिक मामलों में भी जहाँ ऐसे अनुरोधों पर इस प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाता है, मौजूदा दरों में विस्तारित अवधि के लिए तदर्थ कटौती की जाएगी जोकि 3 महीनों से अधिक नहीं होगी। विस्तार प्रदान करना भी इस शर्त के अधीन होगा कि विस्तारित अवधि के दौरान प्रोद्भूत अतिरिक्त अधिशेष, यदि कोई हो, अगले प्रशुल्क संशोधन में पूर्णतः समायोजित किया जाएगा।

- (ii). उस वर्ष के लिए जिसमें अनुमोदित संशोधित प्रशुल्क प्रभावी होगा, यथा लागू डब्ल्यूपीआई और आरओसीई परिगणित किया जाएगा।

आपवादिक मामलों में, जब वित्तीय वर्ष में कोई बदलाव किसी मामले में इस प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिए जाने के समय और ऐसे निर्णय की अधिसूचना की तारीख के बीच होता है, और यदि मध्यवर्ती अवधि में प्रशुल्क दिशा-निर्देशों के अनुसार डब्ल्यूपीआई के मूल्यों और आरओसीई में संशोधन किया जाता है, आरओसीई के लागू मूल्य और वार्षिक वृद्धि कारक ठीक प्रकार से दर्शाए जाने की सीमा तक पूर्ववर्ती प्रशुल्क आदेश की समीक्षा की जाएगी। ऐसी समीक्षा कार्यवाही संबद्ध पत्तन न्यास/निजी टर्मिनल द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर अथवा इस प्राधिकरण द्वारा अपनी ओर से शुरू की जाएगी।

- (iii). संशोधित प्रशुल्क की अधिसूचना की तारीख को प्रचलित विदेशी मुद्रा विनियम दर के आधार पर प्रशुल्क आदेश में सुविचारित वित्तीय स्थिति की समीक्षा की जाएगी, यदि विश्लेषण में विश्वस्त दर और अधिसूचना की तारीख को प्रचलित उस दर के बीच की भिन्नता $(+)/(-)$ 2% से अधिक हो। ऐसी समीक्षा कार्यवाही संबद्ध पत्तन न्यास/निजी टर्मिनल द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर अथवा इस प्राधिकरण द्वारा अपनी ओर से शुरू की जाएगी।

- (iv). लाइसेंस करार के अनुसार निजी प्रचालकों द्वारा किए जाने वाले पूर्व-भुगतान और अग्रिम विविध देनदारियों के लिए उस सीमा तक स्वीकार्य होंगे जहाँ वे पास-थू रूप में अन्यथा स्वीकार्य हों। मूखामी पत्तन को राजस्व हिस्सेदारी/रॉयल्टी का अग्रिम भुगतान विविध देनदारियों के हिस्से के रूप में स्वीकार्य होगा केवल यदि उस सीमा तक तब ऐसी राजस्व हिस्सेदारी/रॉयल्टी प्रशुल्क में पास-थू रूप में सुविचारित की जाती है।

- (v). पत्तन न्यासों और निजी टर्मिनल प्रचालकों को किसी वर्ष की प्रत्येक तिमाही के पूरा होने के 15 दिनों के भीतर वास्तविक प्रत्यक्ष और वित्तीय निष्पादन की रिपोर्ट भेजी जाए। ऐसी तिमाही रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष के 30 जून, 30 सितम्बर, 31 दिसम्बर और 31 मार्च को समाप्त अवधि के लिए उसी प्रारूप में भरे जाते हैं जिसमें प्रशुल्क प्रस्तावों के लिए लागत विवरण भरे जाते हैं। रिपोर्ट के साथ प्रभावी प्रशुल्क निर्धारित करने के लिए विश्वास किए गए अनुमानों से भिन्नता के कारण भी होने चाहिए। यदि दो क्रमिक तिमाही अवधि के लिए वास्तविक और अनुमानों के बीच $(+)/(-)$ 20% की भिन्नता देखी जाती है तो यह प्राधिकरण संबद्ध पत्तन न्यास/निजी टर्मिनल प्रचालकों को प्रशुल्क की अनुसूची समीक्षा किए जाने के लिए अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहेगा। यदि संबद्ध पत्तन न्यास अथवा निजी टर्मिनल प्रचालक इस प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली समय-सीमा के भीतर प्रशुल्क प्रस्ताव दाखिल करने में असफल रहता है, प्रशुल्क की समीक्षा करने के लिए अपनी ओर से कार्यवाही शुरू की जाएगी।

**TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS
NOTIFICATION**

Mumbai, the 24th October, 2008

No. TAMP/23/2003-WS.—In exercise of the powers conferred by Sections 48, 49 and 50 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby notifies refinement on certain areas of the existing approach/practice followed in tariff setting exercise of major port trusts and private terminals operating at the major port trusts as in the Order appended hereto.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

Case No. TAMP/23/2003-WS

ORDER

(Passed on this 30th day of September, 2008)

In the tariff proceeding concerning a review petition filed by a private terminal operator, this Authority observed the need to improve / refine on certain areas of the existing approach adopted and practice followed for tariff fixation, under cost plus approach, bearing in mind the tariff guidelines notified by this Authority on 31 March 2005 vide Gazette No. 38, dated 31 March 2005.

2. The following areas of the existing approach adopted and practice followed in fixation of tariff under cost plus method emerged for improvement / refinement:

- (A). Submission of tariff proposals;
- (B). Application of Wholesale Price Index (WPI) and Return on Capital Employed (ROCE);
- (C). Foreign Exchange Rate;
- (D). Level of Sundry Debtors to be considered as part of Working Capital;
- (E). Submission of actual and physical performance details;

Since the issues confronted are general in nature, they may equally apply to other private terminals and port trusts.

3. The issues listed above are analyzed below.

(A). Submission of Tariff Proposals:

- (i). Clause 3.1.2 of the tariff guidelines requires this Authority to prescribe a time table for submission of tariff proposals for revision. Till such a time table is prescribed, proposals for revision of the existing tariff shall be forwarded atleast 3 months before the due date for revision. No specific timetable for submission of proposals is prescribed so far.
- (ii). It is observed that in most of the cases, the tariff proposals are not filed before 3 months of the expiry of the current tariff validity cycle. Since proposals are filed on different dates, it becomes difficult to apply a uniform Wholesale Price Index (WPI) rate for escalation, Return on Capital Employed (ROCE) and foreign exchange rate. Besides, actuals for the immediate preceding year are also not furnished by the proposers. For example, a proposal filed in February 2008 and decided in May/June 2008 contains actuals only for the year upto 2006-07, even though the revised rates are applicable from the financial year 2008-09. This leaves the financials for the year 2007-08 not being assessed based on actuals.
- (iii). It is, therefore, necessary to prescribe a cut off time for filing tariff proposals in a financial year. The ports and terminals should file tariff proposals by 30 June of the financial year in which tariff revision falls due. Such proposal should furnish actuals upto the previous financial year. To illustrate, the tariff fixed for ABC port in December 2005 will fall due for revision in December 2008. ABC port should, therefore, file its tariff proposal before 30 June 2008 giving actuals upto the previous financial years 2007-08 and projections for the next tariff validity period of 3 years.

- (iv). Request for extension of validity of the tariff shall not be entertained unless sufficient justifiable reasons are advanced for not filing tariff proposal in time. Even in exceptional cases where such requests are entertained, this Authority will effect an ad hoc reduction in the existing rate and allow it to apply for the extended period which in any case shall not exceed 3 months. Grant of extension will also be subject to the condition that additional surplus, if any, accrued during the extended period will be fully set off in the next tariff revision.

(B) Application of WPI & ROCE

- (i). Clause 2.5.1. of tariff guidelines of 2005 stipulates, inter alia, that the expenditure projections should be in line with traffic adjusted for price fluctuation with reference to current movement of WPI for all commodities announced by the Government of India. Clause 2.9.2. of the tariff guidelines prescribes that the permissible return on capital employed will be reviewed at the beginning of the financial year in the light of changes in the key parameters.
- (ii). This Authority will apply the WPI and ROCE as applicable for the year in which the revised tariff approved will come into force.
- (iii). In exceptional cases, when a change in financial year occurs between the time this Authority decides a case and the date of notification of such decision, and if the values of WPI and ROCE undergo a revision as per the tariff guidelines in the intervening period, the concerned tariff Order will be reviewed to the extent of correctly reflecting the applicable value of ROCE and annual escalation factor.

C. Foreign Exchange Rate

- (i). In the existing arrangement, the foreign exchange rate prevailing at the time of conclusion of the cost analysis of a tariff case by the Authority is considered for drawing up the cost estimates. Even though the tariff guidelines permit the port trusts and the private terminals to prepare their income estimates duly factoring the possible variation in foreign exchange over the next tariff validity period, it is observed that generally income estimates are not drawn considering future changes in foreign exchange. It may be difficult to reliably foresee the fluctuations in foreign exchange market over the next 3 year period.
- (ii). This Authority has already requested the Government to review its policy of denominating certain port tariff items in dollar terms but collected in Indian Rupee. Pending a revised policy decision to be taken by the Government, it may be necessary to atleast account for the fluctuations in foreign exchange that may take place between the time this Authority concludes its analysis and notification of the revised tariff in the Gazette of India. This Authority will carry out a review of the cost estimates considered based on the foreign exchange rate prevailing on the date of notification of the revised tariff, if the variation between the rate relied upon in the analysis and that prevailing on the date of notification is more than (+)/(-)2%. Such a review proceeding can be initiated based on an application made by the concerned port trusts / private terminal or by this Authority *suo motu*.

D. Level of Sundry Debtors to be considered as part of working capital

- (i). Clause 2.9.9. of the tariff guidelines prescribes a limit of two months' estate and railway terminal charges payable by Indian railways as the sundry debtor level to be considered as part of working capital. Since the private terminal operators do not lease out the estate under their possession, no estate related income accrue to them. Likewise, they also do not carry out the railway activity and hence no terminal charges are payable to them by the Indian railways. Consequently, the sundry debtors balance always become zero in the case of private terminal operators. On the contrary, there are certain prepayments and advances which are to be made by the private terminal operators as required by the concerned license agreement. Even though such payments are shown under sundry debtors and advance in the books of accounts of the private operators, they are not recognised for tariff fixing purpose in view of the tariff guidelines.

- (ii). It is noteworthy that clause 2.9.9. of the tariff guidelines permits this Authority to examine the reasonableness of the various items of working capital. The prepayments and advance to be made by the private operators as per the license agreement are inevitable contractual obligation. It is, therefore, reasonable to recognise such payment as the limit for sundry debtors to the extent they are otherwise permissible as pass through. In order to avoid any ambiguity, it is clarified that advance payment of revenue share / royalty to the landlord port will be recognised as a part of sundry debtors only if and to the extent such revenue share/royalty is considered as pass through in tariff.

E. Submission of actual physical and financial performance details :

- (i). Clause 2.13. of the tariff guidelines requires the actual physical and financial performance to be reviewed at the end of the prescribed tariff validity period and adjust the variation prospectively in the prescribed manner. It is observed that carrying out such a review after three years period may not provide early relief to the major port trust / private terminals operating thereat or the users, as the case may be, if significant variation is observed in the early phase of the tariff validity cycle. It may, therefore, be a better arrangement to put in place a system for continuous monitoring.
- (ii). The port trusts and private terminal operators are required to furnish a report of the actual physical and financial performance within 15 days of completion of each quarter of a year. Such quarterly reports are to be filed for the period ending 30 June, 30 September, 31 December and 31 March of each of the year in the same format in which the cost statement for the tariff proposals are filed. The report should also be accompanied with the reasons for variation from the estimates relied upon for fixing the tariff in force. If a variation of (+)/(-)20% is observed between the actual and the estimates for two consecutive quarterly period, this Authority will call upon the concerned port trust / private terminal operators to submit their proposal for an ahead of schedule review of tariff. If the concerned port trust or private terminal operator fails to file a tariff proposal within the time limit to be stipulated by this Authority, *suo motu* proceeding will be initiated to review the tariff.

4. Since the issues analyzed above are only refinement of the existing approach adopted and practices followed for tariff fixation and do not amount to resetting of any of the provisions of the tariff guidelines, no separate consultation process with the stakeholders was undertaken.

5. In the result, and for the reasons given above, and based on a collective application of mind, this Authority decides the following:

- (i). (a). The major port trusts and private terminals should file tariff proposals by 30 June of the financial year in which tariff revision falls due. Such proposal should be accompanied by actuals upto the previous financial year.
- (b). Request for extension of validity of the tariff will not be entertained unless sufficient justifiable reasons are advanced for not filing tariff proposal in time. Even in exceptional cases where such requests are entertained by this Authority, an ad hoc reduction in the existing rates will be effected for the extended period which in any case cannot exceed 3 months. Grant of extension will also be subject to the condition that additional surplus, if any, accrued during the extended period would be fully set off in the next tariff revision.
- (ii). WPI and ROCE as applicable for the year in which the revised tariff approved will come into force will be reckoned with.

In exceptional cases, when a change in financial year occurs between the time this Authority decides a case and the date of notification of such decision, and if the values of WPI and ROCE undergo a revision as per the tariff guidelines in the intervening period, a review of the earlier tariff Order will be undertaken to the extent of correctly reflecting the applicable value of ROCE and annual escalation factor. Such a review proceeding will be initiated based on an application made by the concerned Port Trust / Private Terminal or by this Authority *suo motu*.

- (iii). The financial position considered in a tariff Order will be reviewed based on the foreign exchange rate prevailing on the date of notification of the revised tariff, if the variation between the rate relied upon in the analysis and that prevailing on the date of notification is more than (+)/(-)2%. Such a review proceeding will be initiated based on an application made by the concerned Port Trust / Private Terminal or by this Authority *suo motu*.
- (iv). The prepayments and advance to be made by the private operators as per the license agreement will be recognized as the limit for sundry debtors to the extent they are otherwise permissible as pass through. Advance payment of revenue share / royalty to the land lord port will be recognized as a part of sundry debtors only if and to the extent such revenue share / royalty is considered as pass through in tariff.
- (v). The major port trusts and private terminal operators should furnish a report of the actual, physical and financial performance within 15 days of completion of each quarter of a year. Such quarterly reports are to be filed for the period ending 30 June, 30 September, 31 December and 31 March of each of the year in the same format in which the cost statements for the tariff proposals are filed. The report should also be accompanied with the reasons for variation from the estimates relied upon for fixing the tariff in force. If a variation of (+)/(-)20% is observed between the actual and the estimates for two consecutive quarterly period, this Authority shall call upon the concerned major port trusts / terminal operators to submit their proposal for an ahead of scheduled review. If the concerned port trust or terminal operator fails to file a tariff proposal within the time limit to be stipulated by this Authority, *suo motu* proceeding will be initiated to review the tariff.

BRAHM DUTT, Chairman
[ADVT III/IV/143/2008-Enty.]